भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4903

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: जीरो बजट कृषि

4903. श्री बैन्नी बेहननः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'जीरो बजट' कृषि जो किसानों को हर पहलू से सहायता प्रदान करता है उससे अन्तर्फसल तथा मुख्य फसल उपजाने वाले हरेक किसान को बराबरी से लाभान्वित करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या लघु स्तर या वृहत् स्तर पर कृषि करने वाला प्रत्येक किसान फसल हेतु पर्याप्त निवेश प्राप्त कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार ने कृषि में छद्म बेरोजगारी को इसी प्रक्रिया से पीछे रखा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) अन्तर्फसलन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पद्धति है तथा इसके कई फायदे हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विशेष रूप से किसानों के लिए आर्थिक लाभ में वृद्धि प्रदान करती है। यह मुख्य फसल की विफलता के विपरीत बीमा के रूप में शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में बड़े स्तर पर की जाती है। एकीकृत कृषि प्रणालियों पर अखिल भारतीय समन्वयन अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत कई राज्यों के लिए अन्तर्फसलन प्रणालियों का अध्ययन किया गया है तथा ये किसानों के लिए लाभदायक पाई गई हैं। अन्तर्फसलन जीवित पतवार के रूप में कार्य करती है जिससे खरपतवार तथा जल की आवश्यकता में कमी आती है और किसानों को अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता है। फलीदार फसलों के साथ अन्तर्फसलन जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जेडबीएनएफ) के घटकों में से एक है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारित करके फसल उत्पादकता तथा मृदा उर्वरता में सुधार करता है। इसके अलावा गोबर, गोमूत्र आधारित फार्म्युलेशन तथा जेडबीएनएफ में प्रयुक्त वनस्पति सार इनपुट लागत को कम करने में किसानों की मदद करते हैं।

(ग) जेडबीएनएफ का प्रयोग करने वाले छोटी भू-जोत वाले अथवा बड़ी भू-जोत वाले किसान गाँव अथवा पड़ोस के गाँव से स्थानीय स्तर पर आवश्यक आदानों की खरीद करके खेत पर कम लागत का गोमूत्र अथवा गोबर आधारित खाद तैयार करते हैं।

(घ) देश में छद्म बेरोजगारी पर कोई विशिष्ट समय-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इससे संबंधित आंकड़े सहज रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि, रोजगार एवं बेरोजगारी के तुलनीय समय-वार आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित 'भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति' पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण के रूप में उपलब्ध हैं। पंचवर्षीय सर्वेक्षण के अनुसार अद्यतन उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जुड़ा कार्यबल वर्ष 2009-10 में 24.74 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में 23.18 करोड़, अर्थात लगभग 6 प्रतिशत रह गया है। प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र से माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यबल में बदलाव दुनिया भर के देशों द्वारा अनुभव की गई विकास प्रक्रिया की एक सामान्य घटना है और भारत के लिए भी यही सत्य है। इस बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा गैर-कृषि की अवशोषी क्षमता में कार्य व्यवस्था की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन आता है ताकि कृषि में अब तक जुड़े श्रमिकों के साथ-साथ नवागंतुकों को नए सिरे से समायोजित किया जा सके। सरकार ने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं जो कृषि क्षेत्र को अधिक व्यवहार्य बनाती हैं और जिससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा, सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, सतत निवेश में शामिल विभिन्न परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक करना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी स्कीमों पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

*****